

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्या:- 93/2021

दुर्गाप्रसाद मेघवाल पुत्र औंकारमल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं. 5, पोपरणा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

- अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

- रेस्पोंडेंट

अपील अ0 धारा 22 (क) राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 15.10.2020 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनू उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मैसर्स श्री दुर्गा प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार पपुरना तहसील खेतड़ी बाबत निलम्बित करने प्राधिकार 71/2020

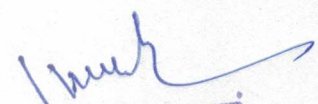
उपस्थित : -

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट - अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री रामावतार, विभागीय पैरोकार - रेस्पोंडेंट की ओर से ।

आदेश

दिनांक:- 03.03.2022


प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के निर्णय दिनांक 15.10.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्त की ओर से अपील निम्न आधारों सहित पेश है कि आदेश दिनांक 15.10.2020 विधिविरुद्ध गलत और अनौचित्य पूर्ण है। जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य गौर नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को नजरअन्दाज किया है। अपीलान्त ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। अपीलान्त को


जिला कलक्टर झुंझुनू

AY
2


उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी मे अलोट हुई थी जिसका सुचारु रूप से अपीलान्ट द्वारा वितरण सामग्री करता आ रहा था। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 है जिसमे अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पपुरना का लाईसेन्स गलत तौर पर निरस्त कर दिया गया था जबकि अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं थी तथा ना ही कोई कमी पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.10.2020 के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे सिविल पीटिशन संख्या 11022/2020 पेश की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2021 को आदेश पारित किया गया कि— **It is made clear that the remedies available under the Rajasthan Food Grains and Other Essential Commodities (Act of Distribution) Order 1976, the shops in question shall not be allotted to any third person.** माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष दिनांक 04.10.2021 को प्रार्थना पत्र मय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई थी तथा रसद अधिकारी को भी पेश की गई थी परन्तु उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय मे अतिशीघ्र पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिये जाने का आदेश जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को दिया जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य पर गौर नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को नजरअन्दाज किया है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। अपीलान्ट को उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी मे अलोट हुई थी जिसका सुचारु रूप से


जिला कलेक्टर झुंझुनूं

अपीलान्ट द्वारा वितरण सामग्री करता आ रहा था। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 है जिसमे अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पपुरना का लाईसेन्स गलत तौर पर निरस्त कर दिया गया था जबकि अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं थी तथा ना ही कोई कमी पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.10.2020 के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे सिविल पीटिशन संख्या 11022/2020 पेश की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2021 को आदेश पारित किया गया कि— It is made clear that the remedies available under the Rajasthan Food Grains and Other Essential Commodities (Act of Distribution) Order 1976, the shops in question shall not be allotted to any third person.” माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष दिनांक 04.10.2021 को प्रार्थना पत्र मय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई थी तथा रसद अधिकारी को भी पेश की गई थी परन्तु उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय मे अतिशीघ्र पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिये जाने का आदेश जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को दिया जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

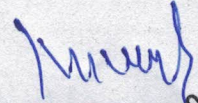
विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट को दूसरे डीलर की दुकान अस्थाई अटैचमेन्ट पर दी गई थी। जांच मे अपीलान्ट द्वारा कम तोलने की शिकायत सही पाई गई। बाट व माप भी जांच मे सही नहीं पाये गये। मौके पर जांच के दौरान भौतिक सत्यापन मे 169 किलोग्राम चीनी व 1057 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये। अपीलान्ट के विरुद्ध जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। मौके पर बनाई गई फर्द पर अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य


जिला कलक्टर झुंझुनूं

नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्त में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। हम विभागीय प्रतिनिधि के इन कथनों को उचित मानते हैं कि जांच में अपीलान्त द्वारा कम तोलने की शिकायत सही पाई गई है। बाट व माप भी जांच में सही नहीं पाये गये हैं। मौके पर जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में 169 किलोग्राम चीनी व 1057 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये हैं। अपीलान्त के विरुद्ध जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। मौके पर बनाई गई फर्द पर अपीलान्त स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्त द्वारा राशन वितरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्त में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज की जाती है। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू